में जलपूर्ति, मल-निर्यास सुविधाएं और बिजली मुहैया की जाती है।

Strike by DDA Karamchari Union

807. SHRI M. KADHARSHA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Cha-turth Aur Tritya Shreni Karamchari Union of the D. D. A. recently were on an indefinite strike; and

(b) if so, what are their demands and what action have been taken t: reon?

THE MINISTER OF STATE I THE MINISTRY OF URBAN DEVE LOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) According to the D. D. A., Union went on a strike on 19-10 which was, however, deferred on the same day.

(b) A list of the demands of the Union is given in the enclosed Statement. (See below).

According to the D. D. A., the matter is before the Deputy Labour Commissioner, Delhi Administration, who is acting as a Conciliation Officer in "the matter.

Statement

Charter of Demands of Chaturth Aur Tritya Shreni Union of Delhi Development Authority

1. Implementation of the settlement dated 30-4-1986.

2. Implementation/finalisation of the issues raised in the strike notice dated 910-1986.

3. No bifurcation of the D. D. A. in various parts/establishment like Housing Board, Slum Board etc.

4. Conversion of daily wages in the workcharged establishment.

S. Payment of Ex-gratia in lieu of bonus on the basis of productivity linked scheme for the year 1986-87 and arrears of previous years.

6. Increase of F. T. A. to Class IV employees and providing FTA to Ministerial/Supervisory staff of class IV and III- at par with other cadres.

7. No absorption of deputationists and no extension beyond normal deputation terms and in the employment.

8. Separate Cadre for Security and Sanitation Departments and promotion in this cadre from the eligible staff.

9. Appointment of the legal heirs of deceased employees.

10. Immediate stoppage of victimisa' tion, discrimination, and step motherly treatment by the management with the DDA cadre officials.

11. Restoration of 5 per cent quota in the built up flats/plots to the DDA employees.

दूरदर्शन कार्यक्रमों के लिए आवंटित समय

808. श्रीमती वीणा वर्मा :
श्री राम चन्द्र विकल :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो सालों में दूरदर्शन पर प्रायोजित और गैर-प्रायोजित कार्यक्रमों को अलग-अलग कितना समय दिया गया; और

(ख) दूरदर्शन द्वारा प्रसारित गैर-प्रायोजित कार्यक्रम कौन-कौन से हैं तथा निकट भविष्य में और कौन-कौन से नये कार्यक्रम प्रसारित किए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजीत पांजा): (क) दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली द्वारा प्रायोजित तथा गैर-प्रायोजित कार्यक्रमों को दिया गया समय इस प्रकार था :

	प्रायोजित (मिनट में)	गैर-प्रायोजित
1986	28,238	2,01,273
1987 (सितम्बर, 87 तक)	14,949	1,54,853

(ङ) प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए कमोवेश नियत चक हैं जहां कार्यक्रम प्रायोजक द्वारा लाया जाता है । दूरदर्शन द्वारा टेली-कास्ट किए जाने वाले अन्य सभी कार्यक्रमों को गैर-प्रायोजित कार्यक्रमों की श्रेणी में रखा जा सकता है । ये कार्यक्रम शिक्षा, बच्चों तथा युवकों, ग्रामीण, महिलाओं, स्वा-स्थ्य, संगीत तथा नृत्य, अपाहिज व्यक्तियों तथा खेलों, आदि जैसे विविध विषयों पर होते हैं । क्योंकि दूरदर्शन द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रमों का निर्माण तथा टेलीकास्ट किया जाना एक सतत प्रक्रिया है, इसलिए इस समय टेलीकास्ट किए जा रहे या भविष्य में टेलीकास्ट किए जाने वाले इस प्रकार के सभी कार्यक्रमों की सूची देना संभव नहीं है ।

Supply of Edible Oil

809. SHRI RAFIQUE ALAM; Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) the position of the edible oil supplies in the country during the remaining months of the current year;

(b) whether any short-fall is expected in supply of edible oils; and

(c) if so, the steps taken by Government to meet the situation?

THE ^MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI H. K. L. BHA-GAT): (a) and (b) The gap between the demand and supply of edible oils in the country is sought to be bridged through imports. Crop estimates for the current year are not available so far. However, due to drought conditions in many of the oilseeds growing States of the country, shortage in the supply of indigenous edible oils may continue.

(c) Government have taken various measures, which are as under:

(i) The allocation of imported edible oil to S*ates/Union Territories under the Public Distribution System and to the vanaspati industry for the manufacture of vanaspati has been increased.

(iii) To cover up the loss in the production of oilseeds due to drought, to the extent possible, contingency plan has been chalked ou-in drought affected States.

(iii) States have been asked to take strict action against borders and speculators in oilseeds/edible oils.

(iv) The network of Fair Price Shops is being strengthened through State Governments especially in the drought affected States.

(v) It has been decided that State Trading Corporation should release imported edible oils in open market by auction for improving availabili ty besides the PDS.

किशोर न्याय अधिनियम का प्रवर्तन

810. **श्रीमती रत्न कुमारी** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किशोर न्याय अधिनियम, 1986 को विभिन्न प्रदेशों में कब से लागू किया जायेगा ;

(ख) इस अधिनियम को लाग करने के लिए सरकार कितना वित्तीय भार उठा रही है ;

(ग) क्या सरकार इस अधिनियम के लागू किए जाने के लिए शत-प्रतिशत वित्तीय भार उठाने का विचार रखती है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाज पेयी) : (क) अधि-नियम 2अक्तूबर, 1987 से, जम्मू और काश्मीर को छोड़कर सारे देश में लागू किया गया है ।

(ख) किशोर सामाजिक कुसमंजन के निवारण और नियंत्रण के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना तैयार की गई है और राज्यों को परिचालित की गई है, जिन से अपेक्षा की जाती है कि वे किशोर न्याय अधिनियम के प्रभावी प्रवर्तन के लिए अवसंरचना के सृजन उन्नयन और सुदृढ़ बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता हेतु प्रस्ताव भेजें । पर्यवेक्षण गृहों, किशोर गृहों और विशेष